भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 671

जिसका उत्तर 8 फरवरी, 2022/19 माघ, 1943 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती अनर्जक आस्तियां

671. श्री राम नाथ ठाकुर
श्रीमती छाया वर्मा
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
चौधरी सुखराम सिंह यादव

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009 से वर्ष 2021 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का परिचालन लाभ दर्ज किया है और चूककर्ताओं के अशोध्य ऋणों के निपटान पर 14 लाख 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2014 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों में कई गुणा वृद्धि को रोकने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई आंकड़ें) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2008-09 से वित्त वर्ष 2020-21 (जिसका विवरण अनुबंध में है) के दौरान 17.18 लाख करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया है और उक्त अवधि के दौरान लगभग 14.20 लाख करोड़ रुपये के कराधान के प्रावधान सहित एक समग्र प्रावधान भी किया है। इसके अलावा, ऋणों का निपटान न्यूनतम व्यय पर वसूली को अधिकतम करने का प्रयास करता है और बैंक वसूली की प्रक्रिया को पूरा करने पर किए गए खर्चों, अर्थात् कानूनी व्यय, वसूली एजेंटों को भुगतान की गई फीस आदि, को छोड़कर कोई खर्च नहीं करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी का कुल सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2008 को 18,19,074 करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31.3.2014 को 52,15,920 करोड़ रुपये हो गया। दबावग्रस्त आस्तियों में उछाल के प्राथमिक कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, कुछ मामलों में जानबूझकर चूक/ऋण धोखाधड़ी और आर्थिक मंदी रहे हैं। स्वच्छ और पूरी तरह से प्रावधानित बैंक बैलेंस-शीट के लिए 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की उच्च घटनाओं का खुलासा किया। एक्यूआर और बाद में बैंकों द्वारा पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था और दबावग्रस्त ऋणों पर अपेक्षित नुकसान, जिसे पहले पुनर्गठित ऋणों को दिए गए लचीलेपन के तहत प्रावधानीकृत नहीं किया गया था, के लिए प्रावधान किया गया। प्रमुखतः एनपीए के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों की पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, पीएसबी के सकल एनपीए दिनांक 31.3.2015 को 2,79,016 करोड़ रुपये (4.97% का सकल एनपीए अनुपात) से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 को 8,95,601 करोड़ रुपये (14.58% का सकल एनपीए अनुपात) हो गया। सरकार की पहचान, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की रणनीति के परिणामस्वरूप, सकल एनपीए तब से घटकर दिनांक 31.3.2021 को 6,16,616 करोड़ रुपये (9.11% का सकल एनपीए अनुपात) और आगे दिनांक 30.9.2021 को 5,79,011 करोड़ रुपये (8.57% का सकल एनपीए अनुपात) हो गया है।

*****

अनुबंध

वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2020-21 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल परिचालन लाभ का विवरण

राशि करोड़ रुपये में

बैंक	परिचालन लाभ
बैंक ऑफ बड़ौदा[1]	1,67,868
बैंक ऑफ इंडिया	98,999
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	25,855
केनरा बैंक[2]	1,44,567
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	39,136
इंडियन बैंक[3]	95,778
इंडियन ओवरसीज बैंक	46,528
पंजाब एंड सिंध बैंक	12,809
पंजाब नेशनल बैंक[4]	2,10,572
भारतीय स्टेट बैंक[5]	6,18,091
यूको बैंक	42,502
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया[6]	1,68,159
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड[7]	47,077

स्रोत: आरबीआई आंकड़े

1 विजया बैंक और देना बैंक को 1.4.2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित किया गया था।

2 सिंडिकेट बैंक को 1.4.2020 से केनरा बैंक में समामेलित किया गया था।

3 इलाहाबाद बैंक को 1.4.2020 से इंडियन बैंक में

4 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1.4.2020 से पंजाब नेशनल बैंक में समामेलित किया गया था।

5 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का 1.4.2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया।

6 आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का 1.4.2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था।

7 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 21.1.2019 से आरबीआई द्वारा एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

नोट: समामेलित बैंकों के आंकड़े उस संबंधित बैंक के आंकड़ों में शामिल किए गए हैं जिसमें उनका समामेलन किया गया था।

*****